गन्ना किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए राहत पैकेज को मंजूरी

विशेष संवाददाता | नई दिल्ली |

मोदी सरकार ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव से पहले गन्ना किसानों की नाराजगी को कम करने की कोशिशें जारी रखते हुए चीनी उद्योग के लिए 4,500 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अतिरिक्त चीनी उत्पादन को देखते हुए कैबिनेट ने एक विस्तृत पॉलिसी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले और इस साल में गन्ने की पैदावार काफी ज्यादा रही है, जिसके लिए यह काफी अहम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पॉलिसी के तहत शुगर मिलों को ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग के खर्चे के लिए खासतौर से निर्यात में विशेष मदद दी जाएगी।

कैबिनेट का फैसला

- कैबिनेट ने शुगर इंडस्ट्री के लिए ₹4,500 करोड़ के पैकेज को दी हरी झंडी

पटना में नया डमेस्टिक टर्मिनल

केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में गन्ना, रेल, होटल समेत कई अन्य फैसले भी लिए गए। पटना एयरपोर्ट पर नया डमेस्टिक टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी अनुमानित लागत 1216.90 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ ऐसे होटल्स थे, जो बनते-बनते रुक गए थे। पटना का पाटलिपुत्र अशोक होटल और गुलमर्ग का अधूरा होटल इन दोनों को अब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा।

नई टेलिकॉम पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने नई टेलिकॉम पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इसमें टेलिकॉम सेक्टर में लाइसेंसिंग और फ्रेमवर्क, सभी के लिए कनेक्टिविटी, सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार करने में आसानी और नई तकनीक पर जोर, जैसे 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी चीजें शामिल हैं। दूरसंचार क्षेत्र में साल 2022 तक 100 अरब डॉलर का नया निवेश होने और 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही 20 एमबीपीएस की और वायरलाइन और वायरलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 50 एमबीपीएस औसत स्पीड प्राप्त करने के लिए नेटवर्क तैयारी, संचार प्रणालियों और सेवाओं के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में भारत को शामिल करने को लेकर रणनीति बनाई गई है।

GSTN अब सरकारी कंपनी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 फीसदी सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि GSTN यूपीए सरकार के कार्यकाल में बनी थी। उस समय 49 फीसदी सरकार और 51 फीसदी वित्तीय संस्थानों की शेयरहोल्डिंग थी। इन कंपनियों का कैरेक्टर प्राइवेट था, जबकि 49 फीसदी में आधा-आधा केंद्र और राज्य सरकारों का था। अब ये 100 फीसदी सरकारी कंपनी बन जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 300 किमी की नई रेल लाइन को मंजूरी

विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 300 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई लाइन के बनने से छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों को फायदा मिलेगा। कटघोरा और डोंगरगढ़ के बीच बनने वाली इस नई ब्रॉडगेज की इलेक्ट्रिफाई रेल लाइन से छत्तीसगढ़ के कई अछूते रेल संपर्क वाले क्षेत्रों में भी रेल पहुंच सकेगी। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इस तरह का पहला जॉइंट वेंचर होगा। इसपर 5,950 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उल्लेखनीय है कि सरहिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल की रीलाइनिंग के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की गई है।

Navbharat Times
27-09-18.